

## प्रेस विज्ञप्ति

23 जुलाई, 2016

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :-

“देश में दलितों और गरीबों पर अत्याचार चरम सीमा पर है। यह भाजपाई सरकारों व आरएसएस की दलित और गरीब विरोधी मानसिकता व षडयंत्र की पहचान बन गया है। गरीब को आए दिन भाजपा शासन में अत्याचार, अपमान, अपशब्द व बलात्कार जैसी त्रासदियों से जूझना पड़ता है। जुल्मों की इन अनगिनत कहानियों में ‘मौन मोदी’ जी की ‘मूक सहमति’ साफ नजर आती है।

मोदी सरकार की ‘नीयत और नीति’, दोनों में ही खोट है, पर वह भूल गए हैं कि, ‘जो सत्ता की सीढ़ी के लिए दलितों का दिल दुखाओगे, तो सारे समाज से नकार दिए जाओगे’। 24 महीने में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जैसे कि :-

### 1. संविधान स्थापित आरक्षण के साथ छेड़छाड़

आरएसएस प्रमुख, श्री मोहन भागवत द्वारा दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर पुर्नविचार की मांग ने भाजपा-आरएसएस के दलित और गरीब विरोधी चेहरे को बेनकाब कर दिया।

### 2. दलितों की भलाई के बजट में भारी कटौती

साल 2014-15 में कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय बजट में ‘एससी सबप्लान’ में 50,548 करोड़ रु. का प्रावधान किया था। मोदी सरकार ने 2015-16 के बजट में यह राशि घटाकर मात्र 30,850 करोड़ रु. कर दी। साल 2016-17 में इसे थोड़ी सी बढ़ोत्तरी कर 38,832 करोड़ रु. कर दिया गया। यह दलित भलाई के कार्यों को रोकने व कमजोर करने की सीधी दुर्भावना को दिखाता है।

कांग्रेस सरकार ने सर पर मैला ढोने की प्रथा को सदा के लिए खत्म करने व कड़ी सजा देने हेतु ‘मैला ढोने के काम पर निषेध और उनके पुनर्वास कानून, 2013’ (The Prohibition of employment as manual scavengers and rehabilitation bill, 2013) बनाया तथा मैला ढोने वाले सभी कर्मियों के लिए 448 करोड़ रु. सालाना निर्धारित किए। मोदी सरकार ने साल 2016-17 के बजट में इस राशि को कम करके भी मात्र 10 करोड़ रु. कर दिया।

यहां तक कि दलितों और आदिवासियों की ‘मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम’ का बजट भी काटकर 1904.78 करोड़ रु. से मात्र 1599 करोड़ रु. कर दिया।

### 3. दलितों को पंचायती राज संस्थाओं में चुने जाने के अधिकार से वंचित करना

भाजपा शासित हरियाणा व राजस्थान में कानून बना पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू करने से 82 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ने

से वंचित हो गए। खास बात यह है कि 93 प्रतिशत दलित महिलाएं चुने जाने के अधिकार से वंचित हो गई हैं।

#### 4. भाजपा मंत्रियों, नेताओं व समर्थकों की अपमानजनक टिप्पणियों पर कोई कार्यवाही नहीं

भारत सरकार के मंत्री **जनरल वी. के. सिंह** ने तो दलितों की तुलना कुत्तों से कर डाली, पर मोदी सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की।

भाजपा महिला मोर्चा, उत्तरप्रदेश की प्रमुख, **श्रीमति मधु मिश्रा** ने 4 अप्रैल, 2016 को दलितों का अपमान करते हुए यहां तक कह डाला कि जो लोग हमारे जूते पॉलिश करते थे, दुर्भाग्य से आज वो हम पर शासन कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में **दो दलित आईएस अधिकारियों**, रमेश टेटे व शशि कर्णावत ने भाजपा मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधे-सीधे प्रताड़ना का आरोप लगाया, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

**बाबा रामदेव** ने कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी द्वारा दलितों के साथ भोजन करने व गरीब की झोंपड़ी में रात्रि विश्राम करने पर तो 'हनीमून' जैसी घोर अपमानजनक टिप्पणी की। इसकी भर्त्सना करने की बजाए, भाजपा ने बाबा रामदेव का समर्थन किया।

**यूपी के भाजपाई उपाध्यक्ष** ने तो हद ही कर डाली, जब एक राजनैतिक पार्टी की अध्यक्षा को उन्होंने अपमानजनक तरीके से वैश्या बताया।

#### 5. दलित अत्याचारों में बेइंतहाशा बढ़ोत्तरी

मोदी सरकार में दलितों पर होने वाले अत्याचारों में 19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है— साल 2013 में दलित उत्पीड़न के 39,408 मुकदमे दर्ज हुए और 2014 में यह बढ़कर 47,064 हो गए। साल 2015 के आंकड़े यह दर्शाएंगे कि यह बढ़ोत्तरी और मुखर हुई है।

दलित अत्याचार की कई घटनाओं ने तो पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया। भाजपा शासित राजस्थान में 29 मार्च, 2016 को 17 साल की **डेल्टा मेघवाल** की दिल दहलाने वाली हत्या हो या फिर भाजपा शासित **हरियाणा** के रोहतक में एक **20 वर्षीय दलित बेटी** के साथ दो दिन पहले हुई गैंगरेप की घटना हो, भाजपाई सरकारें मूक दर्शक बनी रहीं।

**रोहित वैमुला** जैसे मेधावी दलित छात्र को हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, पर न तो दोषी वाईस चांसलर अप्पाराव पर कोई कार्यवाही हुई और न ही दोनों जिम्मेवार केंद्रीय मंत्रियों, बंडारू दत्तात्रेय व श्रीमति स्मृति ईरानी पर। उल्टा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पी. मुरलीधर राव ने तो रोहित वैमुला की तुलना नक्सलवादियों से कर डाली, पर उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

यह दर्शाता है कि जहां दलितों के दिल में देव बसते हैं, भाजपा नेतृत्व रोज उन पर ताने कसते हैं।

## 6. ऊना, गुजरात में दलित अत्याचार— बर्बरता की एक घोर त्रासदी

11 जुलाई, 2016 को जिस प्रकार से बालू सरवैया व उसके परिवार को नंगा कर बेरहमी से पीटा गया, अपमानित किया गया; यह अपनेआप में दलितों पर बर्बरता की एक नई मिसाल है। इसके विरोध में नौ से अधिक दलित भाईयों ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की और भाजपा सरकार मात्र 4 लाख रु. की मुआवजा राशि देकर अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। क्या गरीब की जान की कीमत इतनी सस्ती है?

एकबार फिर यह मामला कांग्रेस और कांग्रेस उपाध्यक्ष, श्री राहुल गांधी ने उठाया है, जो पीड़ित परिवारों से मिलने गुजरात सबसे पहले गए और उनके साथ न्याय की गुहार लगाई। भाजपा की हठधर्मिता तो सब हदें पार कर गई, जब आज तक न तो प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने और न ही गुजरात की मुख्यमंत्री, श्रीमति आनंदीबेन पटेल ने दलित समाज से माफी मांगी।

देश का दुर्भाग्य यह है कि बात बात पर बोलने वाले प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप हैं। इसीलिए पूरा देश कह रहा है कि :-

**‘दलितों के दर्द पर सिंहासन डोलते हैं,  
मोदी जी तो सिर्फ सत्तासुख के लिए मुंह खोलते हैं।’**